कृपया प्रकाशनार्थ **10 नवंबर 2008**

भाजपा नेता व पूर्व पेट्रोलियम मंत्री श्री.राम नाईक द्वारा 10 नवंबर 2008 को नाशिक में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में वितरीत किया गया निवेदन

डिजल, पेट्रोल और गैस के दर को घटाटो - राम नाईक

नाशिक, सोमवार: ''पिछले सोलह वर्षों में सबसे ज्यादा वढी हुई महंगाई और उसके साथ देश में छाई आर्थिक मंदी ने जनसाधारण की कमर तोड़ दी है . गरीबों का जीना मुश्किल हो गया है. इस जर्जर अर्थिक हालत के लिए सरासर प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह की कॉंग्रेस मोर्चे की सरकार जबाबदार है.. आंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के (क्रुड ऑईल) दर में कमी होने के कारण पेट्रोल पर 5 रुपये प्रति लिटर, डिजल पर 3 रुपये प्रति लिटर और रसोई गैस पर 50 रुपये प्रति सिलेंडर की कमी करना चाहिए'' इस प्रकार की मांग भाजपा नेता व पूर्व पेट्रोलियम मंत्री श्री राम नाईक ने नाशिक में आयोजित एक पत्रकार संम्मलेन में की.

इस संबंध में आगे बोलते हुए श्री राम नाईक ने कहा कि , ''महंगाई के पहिए में पेट्रोल-डिजल की कीमत रफ्तार लाती है. पिछले चार वर्षों में पेट्रोलियम क्षेत्र में सरकार की नीति दिशाहीन हो गई है. जुलाई 2008 में कच्चे तेल की किमत प्रति बैरल 147 डॉलर थी, वो 6 नवंबर 2008 को 56 डॉलर अर्थात आधे से भी अधिक गिरी है. 23 अक्टूबर 2008 को लोकसभा में पेट्रोल-डीजल की कीमत को हफ्तेभर मे कम करने की घोषणां करने के बाद भी सरकार ने अभी तक कुछ नहीं किया है . आम आदमी के नाम पर चुन कर आनेवाली यह सरकार आम आदमी का कितना खयाल रख रही है यह इसका उदाहरण है. ऑगस्ट 2008 में विमानो के लिए इस्तेमाल होनेवाला इंधन (एवीएशन टर्बाईन फ्युएल) का दर 73.67 रुपये प्रति लिटर था तो उसमें समय समय पर कमी कर 5 नवंबर 2008 को 42.98 रुपये प्रति लिटर यानी रु.30.69 रुपये प्रति लिटर (42 टक्के) की कमी की गई है. कहने का मतलब कि आम आदमी द्वारा इस्तेमाल किए जानेवाले पेट्रोल-डिजल-गैस के दर में कमी नही की गई, परंतु पैसेवालों की सुविधा के लिए विमान्नों के इंधन के दर में कमी गई ,यह बहुत ही खेद की बात है. मोटर वाहनों के लिए पेट्रोल 55.07 रुपये प्रति लिटर पर विमान पेट्रोल उसकी अपेक्षा सस्ता अर्थात 42.98 रुपये प्रति लिटर यह अर्थशास्त्र सिर्फ प्रधानमंत्री डॉ.मनमोहन सिंह ही समझ सकते हैं.''

'' राशन कार्ड पर मिलनेवाले किरोसिन और रसोई गैस की आपूर्ति में कमी की वजह से अधिकारियों की नाक के नीचे कालाबाजारी जोरों से चल रही है. महिलांओं के स्वास्थ्य पर भी रसोई गैस की कमी के कारण बुरा असर पड़ रहा है. प्रधानमंत्री वाजपेयी के शासनकाल में रसोई गैस के लिए 1 करोड़ 10 लाख ग्राहकों की प्रतिक्षा सूचि समाप्त कर लगभग 4 करोड़ नए कनेक्शन दिए गए थे जिसकी वजह से महिलाओं का सशक्तिकरण संभव हुआ था. तब सिलींडर भी जल्दी उपलब्ध हो जाता था. उसकी तुलना में आजकी परिस्थिति अत्यंत दयनीय है.'' अपनी बात को आगे जारी रखते हुए श्री. नाईक ने कहा.

..2..

''पूरक इंधन अर्थात इथेनॉल का उत्पादन करने के लिए वाजपेयी के शासनकाल में पहली बार प्रयास प्रारंभ हुआ था. 2003 में गन्ने का अधिक उत्पादन होने के कारण 9 राज्यों में पेट्रोल में 5 प्रतिशत इथेनॉल मिलाकर बेचना अनिवार्य किया गया था. 2004 में बाकी राज्यों में 5 प्रतिशत .तो 2005 में संपूर्ण देश में 10 प्रतिशत इथेनॉल मिलाकर बेचने का निर्णय लिया गया था. परंतु किसानों और देश हित में लिए गए इस निर्णय पर डॉ मनमोनहन सिंह की सरकार ने लीकर लॉबी के दबाव में आकर 2004 से अंमल करना बंद कर दिया. इथेनॉल खरीदने की फिर से शुरुआत होगी ऐसा पेट्रोलियम मंत्रालय के सुत्रों से पता चला पर ऐसा नहीं हुआ. पुर देश की दृष्टि से महत्वपूर्ण 4 वर्ष बरबाद हुए . केंद्र सरकार में महाराष्ट्र के श्री शरद पवार कृषि मंत्री और श्री मुरली देवरा पेट्रोलियम मंत्री हैं पर दुर्भाग्य से वे कुछ नहीं कर पाए. 2007-08 के वित्तीय वर्ष में विदेश से 2,72,699 करोड़ के कच्चे तेल का आयात किया गया. अगर 10 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण का कार्यक्रम चालू रहता तो करोडो की विदेशी मुद्रा की बचत होती.साथ ही किसानों और गांवों की आर्थिक हालत भी सुधरती.'' श्री नाईक ने आगे बोलते हुए कहा.

''इसके अलावा जत्रोपा, करंज, पोंगमिया आदि अखाद्य तेल बिजों से जैविक इंधन (बायोफ्युएल) निर्माण करने का सफल प्रयोग वाजपेयी सरकार के समय होने के कारण जत्रोपा का उत्पादन बड़े पैमाने पर करने के निर्णय लिया गया था. परंतु प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार ने जो नालायकीपन दिखलाई है वह अक्षम्य है. जैविक इंधन की एक राष्ट्रीय नीति तय करने के लिए कृषिमंत्री श्री. शरद पवार की अध्यक्षता में एक केंद्रिय मंत्रीमंडल के अध्ययन दल की स्थापना की गई थी. संबंधित अध्ययन दल ने 4 वर्षों में जिस रिपोट को तैयार किया उसे ा 3 नवंबर 2008 को हुई मंत्रीमंडल की बैठक में मंजूरी नही मिली. और उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज किया गया. कहने का मतलब कि जैविक इंधन से संबंधित नीति अधर में लटक रही है. इसके क्रियान्वयन की बात दूर की है.'' श्री नाईक ने बात को स्पष्ट करते हुए कहा.

''थोक बाजार में कीमत के आधार पर महंगाई का निर्देशांक 4 अक्टूबर 2008 को समाप्त हुए हफ्ते में 11.44 प्रतिशत बढ़ा. सितंबर 2008 में महंगाई दर मे वृद्धि सबसे ज्यादा है. वित्तमंत्री डॉ. पी. चिदंबरम ने 2008-09 का बजट पेश करते समय राष्ट्रीय विकास दर (जीडीपी) में कम-से-कम 2 आकडे यानी 10 प्रतिशति से भी ज्यादा की घोषणा की थी जो स्वप्न बनकर ही रह गया है. राष्ट्रीय विकास दर 7.7 प्रतिशत रहेगी ऐसी घोषणा रिजर्व बँकने 23 अक्टूबर 2008 को की है. इसका मतलब है देश में आर्थिक मंदी आई है . एक तरफ बढती महंगाई तो दूसरी तरफ मंदी, आम आदमी दोनों के बीच पिस रहा है. 5 रुपये प्रति लिटर, डिजल पर 3 रुपये प्रति लिटर और रसोई गैस पर 50 रुपये प्रति सिलेंडर की कमी नहीं की गई तो जनता आनेवाले समय में कॉंग्रेस को सबक सिखाए बिना नहीं रहेगी,'' श्री नाईक ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा..

(कार्यालय मंत्री)

विशेष : साथ में महंगाई वृद्धि का तुलनात्मक पत्रक संलगन है .